भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2731

बुधवार, 07 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

लू की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता

†2731. श्री अरविंद गणपत सावंत:

श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में लू की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता से निपटने का कोई प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने लू के कारण होने वाली आपदा की गंभीरता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) दोनों से आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए पर्याप्त वित्तपोषण के हकदार के रूप में ग्रीष्म लहरों से होने वाली आपदा को अधिसूचित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार का लू के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सुसज्जित करने का विचार है; और
- (च) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) जी हां।
- (ख) जलवायु परिवर्तन के कारण, वैश्विक स्तर पर वार्षिक तापमान में वृद्धि हो रही है, और इसका प्रभाव भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लू की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता में परिलक्षित होता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा 1961 से 2020 तक के डेटासेट के आधार पर देश भर में लू की स्थिति के रुझान का विश्लेषण किया गया है। सामान्य तौर पर, उत्तरी मैदानों और मध्य भारत के हीट कोर ज़ोन में लू की आवृत्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति है। लू की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता वैश्विक जलवायु परिवर्तन के व्यापक मुद्दे के स्पष्ट संकेतक हैं।

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों का समाधान करना लू के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव लाने और सभी क्षेत्रों में सतत प्रथाओं को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। इस दिशा में, भारत ने इंटरनेशनल सोलर एलायंस तथा कोएलिशन फॉर डिजास्टर-रिसाइलियेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी पहलों के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में एक अग्रसक्रिय भूमिका निभायी है। भारत विकास के लिए न्यूनतम-कार्बन रणनीतियों पर कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से इस दिशा में कार्य कर रहा है।

(ग) जी हां। असामान्य तापमान की घटनाएं मानव शरीर पर गंभीर शारीरिक तनाव ला सकती हैं क्योंकि मानव शरीर एक उचित सामान्य तापमान सीमा के भीतर ही सबसे अच्छी तरह से काम करता है। मानव मृत्यु दर और अत्यधिक गर्मी के कारण होने वाले तनाव के बीच एक स्पष्ट संबंध है। असामान्य रूप से गर्म अवधि के दौरान, विभिन्न कारणों से होने वाली मौतों का जोखिम, अन्य लोगों की तुलना में बुजुर्गों पर अधिक हो सकता है।

लू के अत्यधिक प्रभाव से होने वाले चार सामान्य लू स्वास्थ्य प्रभावों में निर्जलीकरण, ऐंठन, थकावट और लू लगना शामिल हैं। यह भी जानकारी मिली है कि उच्च तापमान के चलते भोजन के खराब होने और इसकी शेल्फ लाइफ कम होने के कारण एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस और फूड पॉइजनिंग के मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अत्यधिक तापमान वृद्धि के कारण चिंता, धड़कन, घबराहट और व्यवहार परिवर्तन के मामलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यह पाया गया कि अधिकांश पीड़ित कृषि श्रमिक, तटीय समुदाय के निवासी और गरीबी स्तर श्रेणी से नीचे रहने वाले (बीपीएल) थे, जो ज्यादातर घर के बाहर वाले काम-काज करने वाले थे।

(घ) वर्तमान में, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) / राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में 12 आपदाएं नामतः चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सुनामी, ओला तूफान, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला तथा तुषार एवं शीत लहर शामिल हैं। आपदाओं की वर्तमान अधिसूचित सूची में और अधिक आपदाएं शामिल किये जाने के मुद्दे पर 15वें वित्त आयोग में विचार किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8.143 में कहा था कि राज्य आपदा मोचन शमन निधि (SDRMF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन शमन निधि (NDRMF) से वित्त पोषण हेतु पात्र अधिसूचित आपदाओं की सूची काफी हद तक राज्य की जरूरतों को कवर करती है, और इस प्रकार इसके सीमा-क्षेत्र को विस्तारित किये जाने के अनुरोध को योग्य नहीं माना गया।

तथापि राज्य सरकारें कुछ निर्धारित शर्तों और मानदंडों को पूरा करने के अधीन एसडीआरएफ के वित्त पोषण के लिए निधिवाआबंटन के 10% तक का उपयोग उन प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती हैं। मानत 'आपदा' जिन्हें वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जो प्राकृतिक आपदाओं की केंद्रीय रूप से अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।

(ङ) जी हां।

(च) भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के साथ समन्वयन में निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिससे लू समेत प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के दौरान जान-माल की हानि को कम करने में सहायता मिली है। इनमें शामिल हैं:

- i. तापमान तथा लू संबंधी स्थितियों का ऋतुनिष्ठ तथा मासिक आउटलुक, और उसके पश्चात विस्तारित अवधि पूर्वानुमान जारी करना। पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान संबंधी जानकारी समय पर जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित की जाती है।
- ii. भारत में जिला-वार लू सुभेद्यशीलता एटलस, जिससे राज्य सरकार प्राधिकरणों एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियां को योजना बनाने में सहायता मिल सके।

- iii. भारत में गर्म मौसम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का विश्लेषण मानचित्र, जिसमें दैनिक तापमान, हवा तथा आर्द्रता की स्थितियां शामिल हैं।
- iv. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा राज्य सरकारों के साथ सहयोग से लू की स्थितियों की अधिक संभावना वाले 23 राज्यों में संयुक्त रूप से हीट एक्शन प्लान (HAPs) क्रियान्वित किए गए।

ग्रीष्म ऋतु के शुरू होने से काफी पहले राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लू की तैयारी संबंधी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाती है, तथा पूरी ऋतु के दौरान समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।